

राजा बहादुर गिरिवर प्रसाद नारायण सिंह

बनाम

दुखू लाल दास और अन्य

20 अप्रैल, 1967

मुख्य न्यायाधिपति के. एन. वांचू, वी. भार्गव और जी. के. मीतर,

न्यायाधिपतिगण

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (सं. 30 सन 1950), धारा 3 और 4- अधिसूचना जिसके द्वारा संपत्ति को निहित करने हेतु आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई, जिनको समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया-प्रभाव-निहित करने की तिथि।

वादी/ प्रत्यर्थी ने एक पट्टा प्रतिवादी 1/ अपीलार्थी से प्राप्त किया। प्रतिवादी 1/ अपीलार्थी की संपत्ति में कुछ अधिकारों का, और उसे पट्टे के पैसे का भुगतान कर दिया। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के अनुसार, प्रतिवादी 1/अपीलकर्ता की संपत्ति बिहार भूमि सुधार अधिनियम के तहत प्रतिवादी 2-राज्य में निहित कर दी गई थी। इसके बाद, राज्य ने वादी को पट्टा-राशि का भुगतान करने के लिए कहा, जिसका वादी ने विरोध करते हुए भुगतान किया। वादी ने प्रतिवादियों में से किसी एक से पट्टा-राशि की वापसी का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर

किया, जिसे उसे प्रत्येक प्रतिवादी को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने राज्य के खिलाफ मुकदमे का फैसला सुनाया। राज्य ने अपील की, और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को पैसे वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया और राज्य के खिलाफ डिक्री को रद्द कर दिया।

अवधारित: - प्रथम प्रतिवादी को पट्टा-राशि एकत्र करने का अधिकार था, न कि राज्य को।

अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार जब अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जबकि यह दो समाचार पत्रों में अपेक्षानुसार कोई प्रकाशन नहीं हुआ। इस चूक के कारण आवश्यक प्रावधानों की अनुपालना नहीं हुई जबकि कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशन की आवश्यकता है। अधिनियम का धारा 5(ए) उस समय लागू नहीं हुआ और परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नंबर 1 निरंतर स्वामी रहा और उस स्तर पर इस अधिसूचना द्वारा संपत्ति में उसको अधिकारों से वंचित नहीं किया गया। इस मामले के रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी यह दिखाने के लिए कि अधिसूचना बाद में भी किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी; लेकिन, निचली अदालतों में, मामला प्रतिवादी 1 द्वारा स्वयं स्वीकृति के आधार पर आगे बढ़ा कि उसे बाद की तारीख में बेदखल कर दिया गया था और यह बाद की तारीख से प्रभावी था तथा देर से उसे उसके मालिकाना अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। नतीजतन, वह बुरा था। संबंधित पूर्व तिथि

पर वादी को पट्टा देने का पूर्ण अधिकार और उस पट्टे के तहत अधिकारों का प्रयोग वादी द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब प्रतिवादी सं.1 अभी भी मालिक था। [1772 एच-773 डी]

अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) में निर्देश दिया गया कि दो समाचार पत्र के कम से कम दो बार अधिसूचना प्रकाशन किया जाना अनिवार्य था, न कि केवल निर्देशिका। अधिसूचना का दूरगामी असर हुआ. इसने मालिक को संपत्ति के मालिक के रूप में उसके निहित अधिकारों से वंचित कर दिया और उन अधिकारों को राज्य सरकार में निहित कर दिया। अधिकारों में यह परिवर्तन एक मालिक की व्यक्तिगत संपत्तियों के संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा लाया जाना था और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिसूचना के इस महत्व के कारण विधायिका ने इसे पर्याप्त नहीं माना कि अधिसूचना को प्रकाशित किया जाना चाहिए, यदि विधायिका की मंशा यह थी कि दोनों में प्रकाशन हो के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है । अधिनियम की धारा 4(ए) के मुख्य भाग में यह आशय स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता था कि धारा 4 स्वयं परिणाम " आधिकारिक राजपत्र में धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर" उत्पन्न होने वाले थे । इस खंड में "प्रकाशन" शब्द को अर्हता प्राप्त नहीं करने से "आधिकारिक राजपत्र में" विशेषण खंड के साथ, विधायिका को स्पष्ट रूप

से संकेत दिया जाना चाहिए कि अधिसूचना को धारा 3 के उप-धारा (2) में निर्धारित तरीके के अनुसार पूरी तरह से प्रकाशित किया जाना चाहिए। अधिनियम का जहां तक निहित करने की तारीख का सवाल है, इसकी परिभाषा स्वाभाविक रूप से उप-धारा में परिकल्पित सभी पांच न्यूनतम प्रकाशनों पर निर्भर नहीं हो सकती है। धारा 3 के उप-धारा (2) में इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि अधिसूचना का प्रकाशन उन दोनों अंकों में से किसी में भी हो। समाचार पत्रों में अधिसूचना उसी तिथि को प्रकाशित होगी जिस दिन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होगी और न ही इस बात की कोई निश्चितता हो सकती है कि अन्य समाचार पत्र के दो अवसरों पर भी अधिसूचना उसी तिथि को प्रकाशित होगी। इन परिस्थितियों में, राज्य सरकार में प्रभावी उस सटीक तारीख को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना आवश्यक था जिससे संपत्ति का अधिकार प्राप्त होगा। यही कारण है कि 'निहित होने की तारीख को अधिनियम में परिभाषित किया गया था। अधिनियम की धारा 2(एच) में यह निर्धारित किया गया है कि निहित होने की तारीख आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख होगी। इसलिए, यह परिभाषा यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल की गई थी कि 'प्रत्येक मामले में निहित होने की तारीख बिना किसी अनिश्चितता या अस्पष्टता के निर्धारित की जा सकती है और अधिसूचना वास्तव में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित कम से कम दो

समाचार पत्रों के दो अवसरों पर प्रकाशित होने के बाद ही निहित होगी,।

[764 एफएच 765 एफ-766ई]

तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) का संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था। भूलक्षी प्रभाव किए जाने से केवल यह निष्कर्ष निकल सकता है कि, यद्यपि विधायिका ने, संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, लेकिन इसने उन अधिसूचनाओं को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं बनाया, जिनके संबंध में वहाँ उप-धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा था। धारा 3 (2) दो समाचार पत्रों के दो अवसरों पर प्रकाशन को छोड़ कर। [770 ईजी]

रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, रामपुर ,
[1965] 1 एससीआर 970, संदर्भित।

रबाती रंजन और अंत-। बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1953 पटना
121, अस्वीकृत.

निर्णय: सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 91
1./1964:

पटना उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 398/1957 में पारित
निर्णय और आदेश दिनांकित 1 नवंबर 1961 के फैसले और डिक्री के
खिलाफ अपील।

प्रतिवादी संख्या 1-9 के लिए बी. सेन और यूपी सिंह, बीआरएल अयंगर के लिए और एसएन मुखर्जी

न्यायाधिपति भार्गव-

यह अपील बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (1950 की संख्या 30) (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधान की व्याख्या का प्रश्न उठाती है, जो प्रारंभ में 11 सितंबर, 1950 को लागू हुआ था। 12 मार्च, 1951 को, इस अधिनियम को पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर शून्य घोषित कर दिया गया कि इसके प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। 18 जून, 1951 को संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद 6 नवंबर, 1951 को अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की गई। प्रतिवादी नंबर (इस अपील में अपीलकर्ता) की संपत्ति के संबंध में अधिनियम के 3 (1) में यह घोषणा की गई है कि प्रतिवादी नंबर की संपत्ति राज्य में पारित हो गई है और 1 उसमें निहित हो गई है। अधिसूचना 14 नवंबर, 1951 को बिहार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। यह विवादित है कि क्या यह उस समय किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1 ने सम्पदा पर कब्जा जारी रखा। 12 अप्रैल, 1952 को प्रतिवादी सं.1 ने वादी को (अब इस अपील में उत्तरदाताओं 1 से 9 तक प्रतिनिधित्व किया है) प्रतिवादी नंबर की संपत्ति में स्थित भूमि में बीड़ी पत्तियों के संग्रह के लिए तीन साल के

लिए पट्टा दिया। यह आम बात है कि बीड़ी पत्तियों का संग्रह 1 मई से शुरू होता है। और 15 जून, ताकि, वर्ष 1952 के लिए, वादी को 1-5-1952 और 15-5-1952 के बीच बीड़ी के पत्ते इकट्ठा करने थे। पट्टे की शर्तों के तहत, वादी को रुपये का भुगतान करना होगा। प्रतिवादी नंबर 1 को प्रत्येक वर्ष 22,500/- रुपये और इसके अलावा, रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। 7,500/- सिक्योरिटी के तौर पर वर्ष 1952 के लिए, वादी ने रुपये का भुगतान किया। 30,000/- प्रतिवादी संख्या को 5 मई, 1952 को, इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम वैध और संवैधानिक था। 12 जून, 1952 को, पट्टा दिनांक 12 अप्रैल 1952 को पंजीकृत किया गया। अगले ही दिन, 13 जून, 1952 को राज्य सरकार, प्रतिवादी संख्या 2 (इस अपील में प्रतिवादी संख्या 10) द्वारा एक उदघोषणा जारी की गई। बताया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 की संपत्ति को सरकार ने अधिनियम के तहत अपने कब्जे में ले लिया है। 21 नवंबर 1952 को, प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को कारण बताने के लिए एक नोटिस दिया कि प्रतिवादी संख्या द्वारा उसे पट्टा क्यों दिया गया को रद्द नहीं किया जाना चाहिए. 18 अप्रैल 1953 को, 1 प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को सूचित किया गया कि मौजूदा पट्टेदार के रूप में वह सरकार के अंतिम आदेश पारित होने तक कब्जा जारी रख सकता है। 2 मई, 1953 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी को एक और नोटिस दिया गया कि जब तक वादी प्रतिवादी संख्या, 2 को पिछले वर्ष 1952 की लीज राशि का भुगतान नहीं करता, उसे वर्ष 1953

की लीज नहीं मिलेगी। विरोध के तहत, वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 को 1952 और 1953 दोनों वर्षों के लिए पट्टे की धनराशि का भुगतान 4 जून को किया। 1954. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम 20, 1954 (इसके बाद इसे "संशोधन अधिनियम" कहा गया) लागू हुआ। इस संशोधन का प्रभाव यह होगा कि वादी प्रतिवादी संख्या में से किसी एक के विरुद्ध डिक्री कादावा करेगा। 1 या प्रतिवादी संख्या 2 रुपये की दो रकम के लिए। 7,500/- जो उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पर जमा किये थे और रु. 22,500/- जो उसे दोनों प्रतिवादियों में से प्रत्येक को देने के लिए मजबूर किया गया था। 28 जून, 1957 को ट्रायल कोर्ट ने रुपये की राशि के लिए मुकदमे का फैसला सुनाया। 7,500/- केवल प्रतिवादी संख्या के विरुद्ध और रुपये की राशि के लिए। 22,500/- प्रतिवादी 1 संख्या 2 के विरुद्ध 14 अक्टूबर, 1957 को प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और 13 जून, 1958 को वादी के रूप में प्रतिवादी संख्या की ओर से प्रतिवाद दायर किया गया। उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर, 1961 को अपील का फैसला करते हुए कहा कि प्रतिवादी नंबर के पास कोई 1 अधिकार नहीं था जिसके तहत वह वादी को पट्टा दे सके और इसलिए, न केवल रुपये की राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी था। 7,500/- सिक्योरिटी के तौर पर जमा किए गए, लेकिन साथ ही रु. 22,500/- जो उन्होंने वादी से वर्ष 1952 के लिए लीज मनी के रूप में वसूल किया था। प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का डिक्री, रु। 22,500/- को रद्द

कर दिया गया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 को वर्ष 1952 के लिए भी पट्टा राशि प्राप्त करने का हकदार माना गया था। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर इस अपील में इस अदालत में आया है। 500/- सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन रुपये की राशि भी। 22,500/- जो उन्होंने वादी से वर्ष 1952 के लिए लीज मनी के रूप में वसूल किया था। प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का डिक्री, ₹122,500/- को रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 को वर्ष 1952 के लिए भी पट्टा राशि प्राप्त करने का हकदार माना गया था। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर इस अपील में इस अदालत में आया है। 500/- सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन रुपये की राशि भी। 22,500/- जो उन्होंने वादी से वर्ष 1952 के लिए लीज मनी के रूप में वसूल किया था। प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ ट्रायल कोर्ट का डिक्री, ₹ 22,500/- को रद्द कर दिया गया, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 को वर्ष 1952 के लिए भी पट्टा राशि प्राप्त करने का हकदार माना गया था। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर इस अपील में इस अदालत में आया है।

2. इस अपील में, प्रतिवादी नंबर के विद्वान वकील ने कहा कि वह अब डिक्री को चुनौती नहीं दे रहा है क्योंकि मैं रुपये के भुगतान का निर्देश देता हूं। वादी को दी गई सुरक्षा राशि की वापसी के रूप में 7,500/- रु.

यह स्वीकार किया गया कि कम से कम 13 जून, 1952 के प्रभाव से, प्रतिवादी नंबर अब संपत्ति में स्वामित्व के अधिकारों का दावा नहीं कर रहा था, और चूंकि उसे पहले ही रुपये की पट्टा राशि प्राप्त हो चुकी थी। वादी से वर्ष 1952 के लिए 22,500/- रू., सुरक्षा की अब आवश्यकता नहीं थी। नतीजतन, इस अपील में हम केवल इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या, वर्ष 1952 के लिए पट्टा राशि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 या प्रतिवादी संख्या 2 को देय थी, और यह प्रश्न स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 तब भी संपत्ति का मालिक था जब उसने 12 अप्रैल को वादी को पट्टा दिया था. 1952 और 13 जून, 1952 तक ऐसा ही रहा, या क्या वह 14 नवंबर, 1951 से संपत्ति का मालिक नहीं रहा, और उस तारीख से संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 में निहित हो गई। इस पहलू पर विभिन्न प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा यह आग्रह करने के लिए दलीलें दी गई कि वह मालिक बना रहे और 14 नवंबर, 1951 के प्रभाव से उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए; लेकिन हमें केवल एक ही आधार से निपटने की जरूरत है, जिसके बारे में हम मानते हैं कि मामला प्रतिवादी नंबर के पक्ष में तय हो जाता है। यह आग्रह करने के लिए कि वह मालिक बना रहे और 14 नवंबर 1951 के प्रभाव से उसे संपत्ति से वंचित न किया जाए; लेकिन हमें केवल एक ही आधार से निपटने की जरूरत है, जिसके बारे में हम मानते हैं कि मामला प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में तय हो जाता है। यह आग्रह करने के लिए कि वह मालिक बना रहे और 14 नवंबर 1951 के

प्रभाव से उसे संपत्ति से वंचित न किया जाए लेकिन हमें केवल एक ही आधार से निपटने की जरूरत है, जिसके बारे में हम मानते हैं कि मामला प्रतिवादी नंबर के पक्ष में तय हो जाता है।

3. जिस आधार पर हम सोचते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 को सफल होना चाहिए, वह यह है कि जब प्रतिवादी 3. संख्या 2 ने 6 नवंबर, 1951 को घोषणा जारी की, तो वह घोषणा केवल बिहार के आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना के रूप में प्रकाशित हुई थी, न कि दो अंकों में दो समाचार पत्र. इस चूक के प्रभाव की सराहना करने के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों और संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए बाद के संशोधनों के प्रभाव को समझाया जा सकता है। धारा 3 और एस का हिस्सा अधिनियम के 4 जो इस उद्देश्य से प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे प्रारंभ में वर्ष 1950 में अधिनियमित किए गए थे, नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

"3 राज्य में संपत्ति या कार्यकाल के रूप में निहित अधिसूचना (1) राज्य सरकार समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी मालिक या किरायेदार की संपत्ति या कार्यकाल समाप्त हो गए हैं और राज्य में निहित हो गए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और बिहार राज्य में

प्रसारित होने वाले दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंक प्रकाशित किए जाएंगे, और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। भूमि पंजीकरण अधिनियम, 1876 (1876 का अधिनियम)

VIII) के तहत बनाए गए राजस्व भुगतान या राजस्व मुक्त भूमि के सामान्य रजिस्ट्रों में दर्ज संपत्ति के मालिक को देय पावती के साथ, या ऐसे मामले में जहां संपत्ति दर्ज नहीं की गई है ऐसे किसी भी रजिस्टर और किरायेदारी धारकों के मामले में, संपत्ति के मालिक को या किरायेदारी के किरायेदार को, यदि कलेक्टर के पास ऐसे मालिकों या किरायेदारी धारकों की उनके पते के साथ एक सूची है, और ऐसी पोस्टिंग होगी ऐसे स्वामी पर अधिसूचना की पर्याप्त तामीत समझी जाएगी पा. जहाँ इस तरह की अधिसूचना इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किरायेदार धारक को डाक द्वारा भेजी जाती है।

(3) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन और पोस्टिंग, जहां ऐसी अधिसूचना डाक द्वारा भेजी जाती है, उपधारा (2) में दिए गए तरीके से, ऐसे मालिकों या किरायेदारों को घोषणा

की सूचना का निर्णायक सबूत होगा जिनके हित हैं अधिसूचना से प्रभावित हैं।"

4. किसी संपत्ति या कार्यकाल को राज्य में निहित करने के परिणाम तत्समय लागू किसी अन्य कानून या किसी अनुबंध में किसी बात के बावजूद। धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्: -

(ए) इस अध्याय के बाद के प्रावधानों के अधीन, ऐसी संपत्ति या कार्यकाल, जिसमें ऐसी संपत्ति या कार्यकाल में शामिल किसी भवन या इमारत के हिस्से में मालिक या कार्यकाल धारक के हित शामिल हैं। और मुख्य रूप से संग्रह के लिए कार्यालय या कचरी के रूप में उपयोग किया जाता है ऐसी संपत्ति या पट्टे के किराये का, और स्वतंत्र, वनों, मत्स्य पालन, जलकरों, टोपियों, बाजारों और घाटों और अन्य सभी सरायती हितों में उनके हितों के साथ-साथ खानों और खनिजों में किसी भी अधिकार सहित सभी उप- मृदा में उनके हित, चाहे खोजे गए हों या अनदेखे या चाहे काम किया जा रहा हो या नहीं, ऐसी संपत्ति या कार्यकाल (रेयतों के हितों के अलावा था रेपतों के अधीन) में शामिल खानों और खनिजों के पट्टेदार के ऐसे अधिकार शामिल हैं, जो निहित होने की तारीख से प्रभावी होंगे, सभी दायित्वों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएगा और ऐसे मालिक या किरायेदार का इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या इसके

तहत स्पष्ट रूप से बचाए गए हितों के अलावा, ऐसी संपत्ति या कार्यकाल में कोई भी हित नहीं रहेगा।

5. हमारे समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया था कि दो समाचार पत्रों के अंकों में अधिसूचना प्रकाशित करने के निर्देश को हमारे द्वारा केवल निर्देशिका माना जाना चाहिए और अनिवार्य नहीं होना चाहिए और परिणामस्वरूप अधिसूचना का प्रकाशन मात्र होना चाहिए। आधिकारिक राजपत्र को एस द्वारा आवश्यक अधिसूचना का प्रकाशन माना जाना चाहिए। अधिनियम के 4. यह सही है, जैसा कि उन्होंने आग्रह किया था कि एस में "करेगा" शब्द का मात्र उपयोग 3 (2) अंततः किसी कानून में किसी विशेष निर्देश के अनिवार्य होने का निर्धारण नहीं करता है और ऐसे मौके आए हैं जब यह माना गया है कि यद्यपि "करेगा" शब्द का उपयोग विधायिका द्वारा किया गया है, विधायिका द्वारा दिया गया निर्देश केवल अभिप्राय है निर्देशिका होना. हालांकि, वर्तमान मामले में, हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि उप-एस में निर्देश। (2) अधिनियम की धारा 3 के अनुसार दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों में अधिसूचना का प्रकाशन केवल निर्देशिका था और अनिवार्य नहीं था। अधिसूचना का दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने मालिक को संपत्ति के मालिक के रूप में उसके निहित अधिकारों से वंचित कर दिया और उन अधिकारों को राज्य सरकार में निहित कर दिया। अधिकारों में यह

परिवर्तन एक मालिक की व्यक्तिगत संपत्तियों के संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा लाया जाना था और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिसूचना के इस महत्व के कारण विधायिका ने इसे पर्याप्त नहीं माना कि अधिसूचना को प्रकाशित किया जाना चाहिए केवल आधिकारिक राजपत्र, इसलिए, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों में प्रकाशन की आवश्यकता वाला खंड शामिल था। इस प्रावधान में, विशेषण उपवाक्य "कम से कम का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करके कि प्रकाशन दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों में होना चाहिए, विधानमंडल ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह समाचार पत्रों में इस प्रकाशन को कितना महत्व देता है। अधिसूचना के प्रकाशन के लिए दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों का उल्लेख किया गया था ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि यह आवश्यकता आवश्यक थी और इसे पूरा किया जाना चाहिए इससे पहले कि अधिसूचना किसी मालिक को संपत्ति में इन अधिकारों से वंचित करने और उन्हें राज्य में निहित करने का प्रभाव डाल सके।

6. इस संबंध में, हमारा ध्यान अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) में निहित "निहित होने की तारीख की परिभाषा पर आकर्षित किया गया था, जो बताता है कि "निहित होने की तारीख" का अर्थ, किसी संपत्ति या स्वामित्व के संबंध में है। राज्य में, ऐसी संपत्ति या कार्यकाल के संबंध में

धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख। यह आग्रह किया गया था कि निहित होने की तिथि केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के संदर्भ में परिभाषित की गई है, दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशन को अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए और धारा 4 के प्रावधान लागू होने चाहिए संपत्ति को केवल आधिकारिक राजपत्र पर अधिसूचना के प्रकाशन पर, जिसने निहित होने की तारीख निर्धारित की थी। हमें नहीं लगता कि इस समर्पण में कोई दम है। यह सही है कि निहितीकरण की तिथि निर्धारित करने के लिए दो मुद्दों वाले समाचार पत्रों में प्रकाशन को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दो समाचार पत्रों में प्रकाशन से संपत्ति को सरकार में निहित किया जा सकता है। यदि विधायिका की मंशा यह थी कि अधिनियम के 4 (ए) के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए दो समाचार पत्रों में प्रकाशन को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, तो इस इरादे को मुख्य भाग में रखकर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता था। एस। 4 स्वयं कि परिणाम आधिकारिक राजपत्र में धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर" आने वाले थे। इस खंड में "प्रकाशन" शब्द को आधिकारिक राजपत्र में "विशेषण खंड" के साथ अर्हता प्राप्त न करके, इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि समाचार पत्रों के उन दोनों अंकों में से किसी में भी अधिसूचना का प्रकाशन उसी तारीख को होगा, जिस दिन अधिसूचना आधिकारिक

राजपत्र में प्रकाशित होती है, और न ही इस बात की कोई निश्चितता हो सकती है कि समाचार पत्रों के उन दोनों अंकों में अधिसूचना का प्रकाशन उसी तारीख को होगा, जिस दिन अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होती है। अन्य समाचार पत्रों में भी अधिसूचना उसी तिथि को प्रकाशित की जाएगी। इन परिस्थितियों में, स्पष्ट रूप से उस सटीक तारीख को निर्धारित करना आवश्यक था जिससे राज्य सरकार में संपत्ति का निहितार्थ प्रभावी होना था। यही कारण है कि निहित करने की तारीख को एस में परिभाषित किया गया था अधिनियम के 2 (एच). और यह निर्धारित किया गया कि निहित होने की तारीख आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख होगी। इसलिए, यह परिभाषा यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल की गई थी कि प्रत्येक मामले में निहित होने की तारीख बिना किसी अनिश्चितता या अस्पष्टता के निर्धारित की जा सके। इस परिभाषा का प्रभाव यह है कि दो समाचार पत्रों के दो अंकों में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख चाहे जो भी हो, निहितीकरण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा। कुछ मामलों में, समाचार पत्रों के दो अंकों में अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पहले हो सकती है और कुछ मामलों में, यह उस प्रकाशन के बाद हो सकती है। अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र और समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशित होने का क्रम चाहे जो भी हो, निहितीकरण केवल आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा। यदि यह बाद में समाचार

पत्रों के अंकों में प्रकाशित होता है, निहितीकरण आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से होगा; लेकिन उप-धाराओं के अनुसार दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों में अधिसूचना वास्तव में प्रकाशित होने के बाद ही निहितार्थ लागू और प्रभावी होगा। (2) अधिनियम की धारा 3।

7. इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर भरोसा किया रजा बुलंद शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम नगर पालिका परिषद, रामपुर जिसमें कहां, एम के तहत। 1916 के यूपी नगर पालिका अधिनियम संख्या ॥ की धारा 131 (3) में निर्धारित तरीके से एक बोर्ड को प्रकाशित करना आवश्यक था। 94, कर लगाने के लिए कार्यवाही करते समय, उप-धारा (1) के तहत तैयार किए गए प्रस्ताव और उप-धारा (2) के तहत तैयार किए गए मसौदा नियमों के साथ-साथ अनुसूची III में निर्धारित फॉर्म में एक नोटिस भी दिया जाएगा। धारा 94(3), जो प्रकाशन के तरीके का प्रावधान करती है, इस प्रकार पढ़ें:-

बोर्ड द्वारा बैठक में पारित प्रत्येक प्रस्ताव, उसके बाद यथाशीघ्र, हिंदी में प्रकाशित एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और जहां ऐसा कोई स्थानीय समाचार पत्र नहीं है, वहां राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित करेगी.

8. उस विशेष मामले में, रामपुर के नगरपालिका बोर्ड, जिसने कर लगाया था, ने प्रस्तावों को हिंदी में एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जो उर्दू में प्रकाशित हुआ था, भले ही राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए कोई विशेष या सामान्य आदेश नहीं दिया गया था। प्रस्तावों को एस के पहले भाग में दिए गए तरीके से भिन्न तरीके से प्रकाशित किया जा सकता है। 94(3). इस न्यायालय ने कहा: "जैसा कि हमने पहले ही कहा है, धारा 131(3) का सार यह है कि प्रस्तावों और मसौदा नियमों का प्रकाशन होना चाहिए ताकि करदाताओं को उन पर आपत्ति करने का अवसर मिले, और यह प्रदान किया गया है जिसे हमने धारा 131 (3) का पहला भाग कहा है; वह अनिवार्य है। लेकिन धारा 94(3) द्वारा प्रदान किए गए प्रकाशन का तरीका जिसे हमने धारा 131 (3) का दूसरा भाग कहा है, ऐसा प्रतीत होता है निर्देशिका हो और जब तक इसका पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जाता है, यह करदाताओं को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पर्याप्त होगा। इसलिए, हमारी राय है कि प्रकाशन का तरीका एस में प्रदान किया गया है। 131 (3) निर्देशिका है। उस निर्णय की सादृश्यता पर। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन का उद्देश्य संबंधित सम्पदा के मालिक किरायेदारों को सूचित करना था, और वह उद्देश्य आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा और इसके अलावा, आगे के प्रावधान के अनुपालन द्वारा, जिसके लिए अधिसूचना की एक प्रति संबंधित मालिक

या किरायेदार को भेजने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया था तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धाराओं को संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है:- इसलिए, हमारी राय है कि प्रकाशन का तरीका एस में प्रदान किया गया है। 131 (3) निर्देशिका है। "उस निर्णय की सादृश्यता पर यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन का उद्देश्य संबंधित सम्पदा के मालिक किरायेदारों को सूचित करना था, और वह उद्देश्य आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा और इसके अलावा, आगे के प्रावधान के अनुपालन द्वारा, जिसके लिए अधिसूचना की एक प्रति संबंधित मालिक या किरायेदार को भेजने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया था तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 3 की उप- धाराओं को संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है:- इसलिए, हमारी राय है कि प्रकाशन का तरीका एस में प्रदान किया गया है। 131(3) निर्देशिका है। "उस निर्णय की सादृश्यता पर यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन का उद्देश्य संबंधित सम्पदा के मालिक किरायेदारों को सूचित करना था, और वह उद्देश्य आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा और इसके अलावा, आगे के प्रावधान के अनुपालन द्वारा,

जिसके लिए अधिसूचना की एक प्रति संबंधित मालिक या किरायेदार को भेजने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया था तथ्य यह है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धाराओं को संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है और उस उद्देश्य को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा और इसके अलावा, आगे के प्रावधान के अनुपालन द्वारा पूरा किया जा सकता है जिसके लिए संबंधित मालिक या किरायेदार को अधिसूचना की एक प्रति भेजने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी गया कि उप-एस. अधिनियम की धारा 3 को संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है:- और उस उद्देश्य को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा और इसके अलावा, आगे के प्रावधान के अनुपालन द्वारा पूरा किया जा सकता है जिसके लिए संबंधित मालिक या किरायेदार को अधिसूचना की एक प्रति भेजने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी गया कि उप-एस. अधिनियम की धारा 3 को संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था संशोधन अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है:-

4. उक्त अधिनियम (बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950) की धारा 3 में-

(ए) उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। ऐसी अधिसूचना की एक प्रति सामान्य रजिस्ट्रों में संपत्ति रिकॉर्ड के मालिक को पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी। भूमि पंजीकरण अधिनियम, 1876 के तहत राजस्व भुगतान या राजस्व मुक्त भूमि का रखरखाव, या ऐसे मामले में जहां संपत्ति ऐसे किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई है और किरायेदार धारकों के मामले में, संपत्ति के मालिक को या किरायेदार को किरायेदारी धारक यदि कलेक्टर के पास ऐसे मालिकों या किरायेदारों की सूची उनके पते के साथ है, और ऐसी पोस्टिंग को ऐसे मालिक पर अधिसूचना की पर्याप्त सेवा माना जाएगा था, जहां ऐसी अधिसूचना भेजी जाती है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे कार्यकाल धारक पर, कार्यकाल - धारक को पोस्ट करें। और

(बी) उप-धारा (3) में शब्द "और पोस्टिंग" को छोड़ दिया जाएगा और हमेशा के लिए हटा दिया गया माना जाएगा और शब्दों, कोष्ठक और अंकों के लिए "जहां ऐसी अधिसूचना उप में प्रदान की गई तरीके से डाक द्वारा भेजी जाती है" धारा (2) शब्द "आधिकारिक राजपत्र में प्रतिस्थापित किए जाएंगे और विलेख को हमेशा प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा।"

इस धारा का खंड (बी) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में संशोधन करता है और दो परिवर्तन लाता है। इन दो परिवर्तनों का प्रभाव यह हुआ कि मालिक या संबंधित किरायेदार, जिनके हित धारा 3 के तहत अधिसूचना से प्रभावित हुए थे, को केवल आधिकारिक में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के कारण घोषणा की सूचना माना जाना था। राजपत्र, यह संशोधन इसलिए पेश किया गया था ताकि यह उस तारीख से माना जाए जिस दिन अधिनियम शुरू में लागू हुआ था, ताकि, भले ही यह संशोधन संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया हो, धारा 3 की उपधारा (3) इसे उस अधिनियम में संशोधित रूप में पढ़ा जाए जो नवंबर, 1951 में प्रासंगिक समय पर लागू था। इस पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर यह आग्रह किया गया था कि केवल आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन, दो अखबारों में प्रकाशन को नजर अंदाज करना, या नोटिस पोस्ट करना, मालिक या

संबंधित किरायेदार को घोषणा के नोटिस का कानून के तहत निर्णायक सबूत बन गया था और परिणामस्वरूप, दोनों के दो अंकों में अतिरिक्त प्रकाशन समाचार पत्रों को अब अनिवार्य नहीं माना जा सकता। मालिक या संबंधित किरायेदार को जानकारी देने का उद्देश्य आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा पूरी तरह से प्राप्त किया गया है, प्रकाशन के किसी भी अन्य तरीके को अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए। हालाँकि, यह प्रस्तुतिकरण इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना में निहित घोषणा न केवल मालिक या संबंधित किरायेदार के अधिकारों को प्रभावित करती है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को भी प्रभावित करती है। अधिनियम के बाद के प्रावधानों से पता चलता है कि मालिक के सुरक्षित लेनदार, राज्य सरकार में संपत्ति के निहित होने के परिणामस्वरूप, अपनी सुरक्षा खो देते हैं और उन्हें एस के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। मालिक द्वारा उन पर बकाया ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 14 इसी प्रकार, मालिकों से खनन पट्टे रखने वाले व्यक्ति राज्य सरकार में संपत्ति के निहित होने और मालिकों से उनके अधिकारों के विनिवेश से प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रावधान भी हैं जो दर्शाते हैं कि अधिसूचना प्रकाशित होने और लागू होने के बाद अदालतों को कार्रवाई करनी होगी या अधिनियम में निर्धारित प्रकृति के मुकदमों पर विचार करने से इनकार करना होगा। अधिनियम की कार्रवाई

3 की उपधारा (2) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है।

9. पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले पर भी भरोसा किया गया रेबती रंजन और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 3(2) का उद्देश्य केवल संबंधित स्वामियों को जानकारी देना है, यह दृष्टिकोण एस के वाक्यांशों द्वारा समर्पित है। 3(1) जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट मालिक या किरायेदार की संपत्ति या कार्यकाल, स्थानांतरित हो गए हैं और उसमें निहित हो गए हैं राज्य" वाक्यांश "पारित हो गए हैं और निहित हो गए है, व्याकरणिक रूप से इसका मतलब यह होना चाहिए कि अधिसूचना जारी होने की तारीख पर संपत्ति का शीर्षक राज्य सरकार में निहित हो जाता है, भले ही प्रकाशन और पोस्टिंग पर विचार किया जा रहा हो। 3 (2) यह भी ध्यान देना जरूरी है कि एस. 2 (एच) राज्य में निहित किसी संपत्ति या कार्यकाल के संबंध में "निहित होने की तारीख" को परिभाषित करता है, उप-धाराओं के अंतर्गत अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि (1) एस. ऐसी संपत्ति या कार्यकाल के संबंध में 3. "सम्मान के साथ, हम उस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत होने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि, इस व्याख्या को देने में, न्यायालय ने कई मुख्य विशेषताओं को नजरअंदाज कर दिया। उप-धारा

(1) के बावजूद, न्यायालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया। धारा 3 में यह बताने के लिए अधिसूचना की आवश्यकता थी कि सम्पदाएं राज्य को हस्तांतरित हो गई हैं और राज्य में निहित हो गई हैं, वास्तविक निहितार्थ केवल राज्य सरकार द्वारा उस घोषणा को जारी करने का परिणाम नहीं था। प्रावधान के परिणामस्वरूप निहितार्थ प्रभावी हुआ अधिनियम के धारा 4 (ए) में यह प्रावधान है कि यह प्रभाव अधिसूचना के प्रकाशन पर लागू होगा। इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि धारा में 4 निर्धारित प्रकाशन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन तक ही सीमित नहीं था। न्यायालय ने उप-धाराओं में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कम से कम" के महत्व की भी सराहना नहीं की। (2) एस. 3 और आगे तथ्य यह है कि यह उप-धारा केवल सामान्य शब्दों में समाचार पत्र में प्रत्यक्ष प्रकाशन नहीं करती है, बल्कि यह निर्दिष्ट करती है कि अधिसूचना कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी चाहिए। ऐसी आवश्यकता विधायिका द्वारा प्रकाशन के इस तरीके पर दिए गए जोर को दर्शाती है। न्यायालय ने इस पहलू पर भी विचार नहीं किया कि "निहित होने की तारीख की परिभाषा अधिनियम के 2 (एच) का उद्देश्य केवल निश्चितता के साथ उस तारीख को निर्दिष्ट करना हो सकता है, जिसमें मालिक को उसके अधिकारों से वंचित किया गया था ताकि उन्हें राज्य सरकार में निहित किया जा सके। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए.

10. इस सिलसिले में दूसरा पहलू यह है कि इस संशोधन अधिनियम के उप-धाराओं में भी संशोधन किया गया। (2) इस अधिनियम के 3 और इस संशोधन द्वारा, दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों में प्रकाशन की आवश्यकता को हटा दिया गया। यह महत्वपूर्ण है कि यह संशोधन, उप-एस में इस चूक को लाता है। (2) एस. अधिनियम के 3 को उस तरीके से पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया जिस तरह से उप-धाराओं में संशोधन किया गया था। (3) एस. 3 को पूर्वव्यापी बनाया गया। यदि संशोधन अधिनियम को पारित करते समय विधायिका की मंशा यह थी कि पहले जारी की गई अधिसूचनाएँ, जो दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशित हुए बिना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि विनिवेश हो सके। संपत्ति में मालिक के अधिकार क्या है। इस संशोधन को भी पूर्वव्यापी बनाकर उस इरादे को आसानी से दर्शाया जा सकता था। तथ्य यह है कि उप-एस का संशोधन. (2) एस 3 को पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया था, इसलिए, केवल यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, हालांकि विधायिका ने संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद, समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, लेकिन उन अधिसूचनाओं को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं बनाया, जिसके संबंध में उप धाराओं की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफलता हुई थी। (2) एस. 3. दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशन को छोड़ कर इस संबंध में, यह

उल्लेख किया जा सकता है कि हमारे समक्ष मामले में, यहां तक कि ट्रायल कोर्ट में भी, यह माना गया है कि उप-धाराओं में संशोधन किया गया है।

(2) एस. 3 समाचार पत्रों में प्रकाशन की आवश्यकता को छोड़ना भी पूर्वव्यापी था और यही वह आधार भी है जिस पर उच्च न्यायालय आगे बढ़ा। तथ्य यह है कि उप-एस में यह संशोधन (2) एस. 3 पूर्वव्यापी नहीं था, इस न्यायालय में इस अपील की सुनवाई के दौरान ही इस पर ध्यान दिया गया था और, चूंकि यह कानून का एक शुद्ध प्रश्न था, इसलिए हमने मामले को इसके आधार पर बहस करने की अनुमति दी, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय में यह महसूस करने में विफलता के कारण कि यह संशोधन पूर्वव्यापी नहीं था, ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष था कि प्रतिवादी नंबर 1 की संपत्ति 14 नवंबर, 1951 की अधिसूचना के आधार पर बिहार राज्य में निहित थी, जो एस के तहत जारी की गई थी। अपील की सुनवाई के दौरान अधिनियम के 3 को चुनौती नहीं दी गई। तथ्यात्मक रूप से, पक्षों की दलीलों से यह प्रतीत होता है कि वादी और प्रतिवादी नंबर की ओर से यह मामला रखा गया था कि 6 नवंबर, 1951 की अधिसूचना केवल 14 नवंबर, 1951 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। लेकिन जहां तक पार्टियों को जानकारी थी, इसे किसी भी अखबार में प्रकाशित नहीं किया गया। विशेष रूप से तथ्यों पर दी गई दलीलें और ट्रायल कोर्ट में उस आधार पर मामला तड़े जाने के बाद, हमने यह सही माना कि उच्च न्यायालय में प्रतिवादी नंबर की ओर से अपने फैसले में की गई चूक की

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कानून की 1 सही व्याख्या के आधार पर प्रतिवादी नंबर के रास्ते में खड़ा होना।

11. तथ्यात्मक पहलू पर आते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि, बाद में वादी ने विशेष रूप से अनुरोध किया है। हालांकि प्रतिवादी संख्या की संपत्ति को प्रतिवादी संख्या 2 में निहित करने की एक अधिसूचना 14 नवंबर के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, 1951, फिर भी इसे न तो दो समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, न ही इसकी एक प्रति प्रतिवादी संख्या को भेजी गई, जैसा कि एस. उस समय बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 3(2). यह दलील वादपत्र के पैरा 13 के खंड (ए) में निहित थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपने लिखित बयान के पैरा में अनुरोध किया कि "जहां तक इस प्रतिवादी को जानकारी है, बिहार राज्य के किसी भी समाचार पत्र में कभी भी कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई, न ही पंजीकृत कवर के तहत कोई नोटिस उसे भेजा गया।" / बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3(2)". प्रतिवादी संख्या 2, अपने लिखित बयान के पैरा 11 में, वादी के पैरा 13 और 14 के उत्तर में अपनी दलील पेश की और ऐसा करते हुए, सामान्य शब्दों में कहा कि वास्तव में, कानून के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया गया था। आगे दलील यह थी कि "यद्यपि खंड (बी) और (सी) में उल्लिखित तथ्य सही हैं, खंड (ए) में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही नहीं हैं। यह सच नहीं है कि

अधिसूचना की प्रति पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गई थी पहली बार जैसा कि इस पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है।" इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह दलील दर्शाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में कोई विशेष दलील नहीं दी है। जिसका उल्लेख वाद पत्र के पैरा 13 में किया गया था। विशिष्ट दलील केवल प्रतिवादी संख्या को भेजी जा रही अधिसूचना की प्रति के संबंध में थी. लिखित बयान के पैरा 13 में भी, केवल सामान्य शब्दों में यह दलील दी जा रही थी कि कानून के प्रावधानों के अनुसार वैध अधिसूचना और प्रकाशन था। जहां तक वादी और प्रतिवादी नंबर का सवाल है, वे केवल अखबारों में 1 प्रकाशन के बारे में अनभिज्ञता जता सकते थे और प्रकाशन न होने के नकारात्मक तथ्य का कोई सकारात्मक सबूत नहीं दे सके। प्रतिवादी संख्या 2 अकेले ही विशेष रूप से दलील दे सकता था कि अधिसूचना दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशित हुई थी, यदि यह सब तथ्य था; लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 ऐसा करने में विफल रहा। प्रतिवादी संख्या 2 अकेले ही विशेष रूप से दलील दे सकता था कि अधिसूचना दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशित हुई थी, यदि यह सच तथ्य था लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 ऐसा करने में विफल रहा। प्रतिवादी संख्या 2 अकेले ही विशेष रूप से दलील दे सकता था कि अधिसूचना दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशित हुई थी, यदि यह सच तथ्य था; लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 ऐसा करने में विफल रहा।

12. इस बिंदु पर साक्ष्य भी केवल प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से ही प्रस्तुत किया जा सका। समाचार पत्रों में वास्तविक प्रकाशन को साबित करें। जहां तक प्रतिवादी नंबर 1 का सवाल है, उसने अपने लिखित बयान में अपनी दलील का समर्थन किया, जब गवाह बॉक्स में उसने कहा कि उसे वर्ष 1951 में किसी भी समाचार पत्र में अपनी संपत्ति को निहित करने की अधिसूचना के प्रकाशन के बारे में जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से ऐसा प्रतीत होता है कि अखबार में इस प्रकाशन को साबित करने के लिए सबूत पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। केवल एक गवाह, राधिका प्रसाद, जो अतिरिक्त कलेक्टर के कार्यालय में कार्यरत थे, को अधिसूचना से निपटने के तरीके को इंगित करने के लिए पेश किया गया था। अपने मुख्य परीक्षण में, उन्होंने जो एकमात्र सकारात्मक साक्ष्य दिया, वह यह था कि 14 नवंबर, 1951 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में नोटिस, नजारत चपरासी के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक पर तामील हेतु भेजा गया था। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि यह किसी अखबार में छपा हो। हालांकि, जिरह में, जब प्रतिवादी नंबर की ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि अखबारों में कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, तो गवाह ने कहा कि वह अधिसूचना 'बिहार संदेश' और 'बिहार समाचार' में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने उस स्तर पर भी यह नहीं बताया कि यह उन दो समाचार पत्रों के दो अंकों में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास

कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं था, न ही अभिलेखों से प्राप्त कोई ऐसा ज्ञान था जिस पर भरोसा किया जा सके। उन्होंने स्वीकार किया कि समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में ऑर्डर शीट में कोई नोट नहीं था, और उनके कार्यालय में समाचार पत्रों की कोई कटिंग नहीं थी। उनके कार्यालय से अखबारों को भुगतान भी नहीं किया गया. उनके आगे के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका ज्ञान उक्त समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में सरकार से प्राप्त एक पत्र से प्राप्त हुआ था। यहां तक कि वह पत्र भी पेश नहीं किया गया और गवाह ने उस पत्र की पूरी बातें नहीं बताई. उन्होंने बस इतना कहा कि सरकार का पत्र उन दो समाचार पत्रों में अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में था। पत्र की यह सामग्री यह नहीं दर्शाती है कि क्या पत्र केवल सरकार को इसे प्रकाशित करने का निर्देश था, या इसमें ऐसी सामग्री शामिल हो सकती है जो यह दर्शाती हो कि इन समाचार पत्रों में अधिसूचना का प्रकाशन पहले ही हो चुका था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जब यह मामला पिछली तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष आया, न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2 को समाचार पत्रों का मुद्दा प्रस्तुत करने का अवसर देने का निर्णय लिया। यद्यपि पर्याप्त अवसर की पेशकश की गई थी, विद्वान वकील, जो प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे सामने उपस्थित हुए, ने उन्हें पेश करने में असमर्थता व्यक्त की। समाचार पत्रों के अंक प्रस्तुत करने में विफलता, जिसमें अधिसूचना प्रकाशित हो सकती थी, केवल यह

अनुमान लगा सकती है कि वास्तव में, ऐसा कोई प्रकाशन नहीं था, विशेष रूप से ऊपर देखे गए साक्ष्य की स्थिति में इन परिस्थितियों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि, वास्तव में, एस द्वारा अपेक्षित दो समाचार पत्रों के दो अंकों का कोई प्रकाशन नहीं हुआ था अधिनियम के 3 (2) जब अधिसूचना 14 नवंबर, 1951 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई, इस चूक के कारण एस के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं हुआ। (2) दो समाचार पत्रों के कम से कम दो अंकों में प्रकाशन की आवश्यकता, जिसके परिणामस्वरूप एस. अधिनियम का 4 (ए) उस समय लागू नहीं हुआ और परिणामस्वरूप, यह माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी नंबर 1 मालिक था और उस स्तर पर इस अधिसूचना द्वारा संपत्ति में उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया गया था। इस मामले के रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सामग्री सामने नहीं आई कि वह अधिसूचना बाद में भी किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, लेकिन, निचली अदालतों में मामला प्रतिवादी नंबर द्वारा स्वयं स्वीकारोक्ति के आधार पर आगे बढ़ा कि उसे 13 जून, 1952 को बेदखल कर 1 दिया गया था और उसी तारीख के प्रभाव से उसे उसके मालिकाना अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। फलस्वरूप उसे 12 अप्रैल को वादी को पट्टा देने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। 1952 और उस पट्टे के तहत अधिकारों का प्रयोग वादी द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था जब प्रतिवादी नंबर 1 अभी भी मालिक था। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी संख्या द्वारा पट्टा राशि की उचित वसूली की गई

थी। वादी से 1. प्रतिवादी क्रमांक 2, जिसमें 13 जून 1952 तक अधिकार निहित नहीं थे, को वर्ष 1952 के लिए लीज मनी वसूलने का अधिकार नहीं था, क्योंकि, जब तक अधिकार प्रतिवादी क्रमांक 2 में निहित थे, तब तक बीड़ी का संग्रहण समाप्त हो जाता है। वादी द्वारा वह वर्ष पूरा कर लिया गया है। इन परिस्थितियों में, अकेले इस आधार पर, प्रतिवादी संख्या 1 रुपये की राशि के लिए डिक्री के संबंध में सफल होने का हकदार है। 22,500/- जिसे वह चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ डिक्री को रद्द करना पड़ा। इसके बजाय, इस राशि के लिए डिक्री प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ रुपये की राशि के रूप में पारित की जानी है। प्रतिवादी संख्या द्वारा 22,500/- की वसूली की गई।

13. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई डिक्री को बहाल कर दिया जाता है। इस मामले की परिस्थिति में, हम समानताओं को इस अपील की अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक महावीर प्रसाद गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।